



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1944 (श10)

(सं० पटना 331) पटना, शुक्रवार, 03 जून 2022

सं० 2/आरोप-01-14/2019-सां०प्र०-4165

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

17 मार्च 2022

श्री अनिल कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 940/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी के विरुद्ध महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 269/2016-17, 806/2014-15 एवं 244/2008-09 में उठाये गये आपत्तियों का निराकरण नहीं करने तथा विभागीय दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने संबंधी आरोप के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2704 दिनांक 31.05.2019 द्वारा आरोप-पत्र (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप निम्नांकित है :-

श्री अनिल कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी को कई विभागीय पत्रों द्वारा नगर परिषद्, मसौढ़ी के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 269/2016-17, 806/2014-15, 917/2013-14 एवं 244/2008-09 में उठाये गये आपत्तियों का बिन्दुवत अनुपालन प्रतिवेदन नगर परिषद्, मसौढ़ी की बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त उसे तीन माह के अन्दर महालेखाकार (ले०ह०), बिहार, पटना को भेजते हुए विभाग को भी एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। तीन माह बीत जाने एवं इस बीच मोबाईल द्वारा वांछित प्रतिवेदन प्राप्त हेतु स्मारित करने एवं उनके द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद न तो अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया और न ही विभाग को ही उपलब्ध कराया गया। विभागीय मासिक बैठकों में भी अनुपालन हेतु उन्हें लगातार निर्देश दिया गया।

विभागीय पत्रांक 87 दिनांक 17.01.2019 द्वारा अनुपालन अबतक न भेजने का कारण स्पष्ट करते हुए तीन दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गई, किन्तु श्री कुमार द्वारा इस संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित नहीं किया गया।

श्री कुमार द्वारा बिहार नगर पालिक अधिनियम, 2007 की धारा-94(1) एवं (2) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-130 की कंडिका-06, 07 एवं 08 का अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निराकरण में अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही विभागीय दिशा-निर्देश का भी अनुपालन नहीं किया गया, जो उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही, गैर जिम्मेवारी एवं विभागीय दिशा-निर्देश के उल्लंघन का द्योतक है।

नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त आरोप-पत्र एवं संचिका में उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित आरोप-पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 11687 दिनांक 26.08.2019 द्वारा

श्री कुमार से स्पष्टीकरण की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 50 दिनांक 15.06.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, इनके स्पष्टीकरण एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8483 दिनांक 18.09.2020 विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 988/स्था0 दिनांक 02.11.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों में से कुछ आरोपों को आंशिक प्रमाणित एवं शेष आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में उल्लेखित किया है कि श्री कुमार को तीन माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (ले0ह0), बिहार, पटना का भेजे जाने का विभागीय निदेश दिया गया। पुनः स्मारित करते हुए इन्हें एक पक्ष के अन्दर महालेखाकार (ले0ह0), बिहार, पटना को भेजे जाने हेतु निदेश दिया गया, परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त अनुपालन प्रतिवेदन नगर परिषद्, मसौढ़ी में अपने पदस्थापन अवधि दिनांक 12.11.2018 तक नहीं भेजा जा सका। संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष में यह भी उल्लेखित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 12.11.2018 को नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी का प्रभार अन्य पदाधिकारी को सौंपने के फलस्वरूप अनुपालन प्रतिवेदन को नगर परिषद् बोर्ड के बैठक में अनुमोदित नहीं करा सके, जिसके फलस्वरूप आरोपी पदाधिकारी के द्वारा भी पूर्व में पदस्थापित तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी के तरह उक्त लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (ले0ह0), बिहार, पटना को नहीं भेजा जा सका।

आंशिक प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा उक्त के आलोक में लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन में मुख्यतया गठित आरोप को ही तथ्यहीन, निराधार एवं तकनीकी रूप से गलत होने का उल्लेख किया है। आगे इनके द्वारा जाँच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया गया है। श्री कुमार द्वारा अपने बचाव में खुद को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी। श्री कुमार के द्वारा अपने लिखित अभिकथन में मुख्यतया गठित आरोप-पत्र को ही तथ्यहीन, निराधार एवं तकनीकी रूप से गलत होने का उल्लेख किया गया है। उनका यह भी कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उन्हें गलत तरीके से चिन्हित कर दण्डित करने के उद्देश्य से आरोप-पत्र गठित किया गया था। श्री कुमार के द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को ही गलत ठहराते हुए उपस्थापन पदाधिकारी एवं संचालन पदाधिकारी पर टिप्पणी की गई है। नियमानुकूल श्री कुमार द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखा जाना चाहिए था। जाँचोपरांत इनके द्वारा उक्त बिन्दुओं को उठाया जाना उचित नहीं है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि तीन माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (ले0ह0), बिहार, पटना को भेजे जाने का विभागीय निदेश दिया गया था। पुनः स्मारित करते हुए आरोपी पदाधिकारी को एक पक्ष के अन्दर महालेखाकार (ले0ह0), बिहार, पटना को भेजे जाने हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु आरोपी पदाधिकारी के द्वारा उक्त अनुपालन प्रतिवेदन अपने पदस्थापन अवधि दिनांक 25.10.2018 तक नहीं भेजा गया।

महालेखाकार द्वारा पत्रांक 14587 दिनांक 20.09.2006 के माध्यम से नगर परिषद् मसौढ़ी के वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन की माँग पत्र प्राप्ति के तीन माह के अंदर की गई थी। श्री कुमार द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् मसौढ़ी के पद पर दिनांक 12.07.2017 को योगदान समर्पित किया गया था। श्री कुमार द्वारा अपने पदस्थापन काल दिनांक 12.07.2017 से दिनांक 25.10.2018 तक यानि एक वर्ष तीन माह तक अंकक्षण से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजे जाने के संबंध में सफल कार्यवाही नहीं की जा सकी।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधान के तहत **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) एवं (ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक** का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अनिल कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 940/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी सम्प्रति उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18),

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 331-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>